RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 05 JUNE TO 11 JUNE 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 37 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

Opec+ की कटौती से नहीं बिगड़ेगी तेल आपूर्ति,
Page 2

मई 2024 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह .73 लाख करोड़ रूपये
Page 3

रिजर्व बैंक के आंकड़ें बता रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड बढ़ गया 708 प्रतिशत तो बैंक फ्रॉड 300 प्रतिशत
Page 4

editoria!

जनता ने दिया सरप्राइज

एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जरूर कई लोगों को चौंकाया होगा। नतीजों ने बताया कि राजनीतिक पंडित कितने भी गुणा-गणित और विश्लेषण कर लें, कई बार वे जनता का मूड भांपने में गलती कर जाते हैं। इनमें भी सबसे अधिक हैरान किया 80 सीटों वाले यूपी ने। 2014 और 2019 में BJP को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने में इस राज्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार यहां BJP और I.N.D.I.A. में करीब-करीब बराबरी का मुकाबला दिखा, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। बिहार, कर्नाटक और बंगाल में भी BJP को नुकसान उठाना पड़ा। इनमें से बिहार और कर्नाटक में पार्टी ने पिछले चुनावों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। इन चुनावों में कई रीजनल पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसी तरह NDA के घटक दलों को भी नई ऑक्सिजन मिली है। उनकी बारगेनिंग पावर बढ़ गई है। एग्जिट पोल्स में अकेले BJP को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाया गया था। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के इकलौते राजनेता बन जाते, जिनके नेतृत्व में हर जीत पहले से बड़ी होती गई। लेकिन, चुनाव परिणाम इकतरफा नहीं रहा। NDA और I.N.D.I.A. दोनों के पास जश्न मनाने के लिए कुछ न कुछ है। सीटों के लिहाज से BJP को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने प्रदर्शन से सबको सरप्राइज किया। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ा। वहीं, गुजरात और मध्य प्रदेश BJP के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की सियासत में अब भी ब्रैंड मोदी सबसे बड़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास इतनी भी सीटें नहीं थीं कि वह सदन में विपक्ष का आधिकारिक दर्जा हासिल कर सके। लेकिन, कांग्रेस ने वापसी कर जाहिर कर दिया कि देश में BJP को टक्कर देनी है तो उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इस चुनाव में कांग्रेस ने कई जगह गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका निभाई। लेकिन, I.N.D.I.A. को जितनी सीटें मिलीं, उससे पार्टी का कद जरूर बढ़ेगा। शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन और असली शिवसेना किसकी? क्या माया और ममता अब भी ताकतवर हैं? यह चुनाव ऐसे ही कई सवालों के साथ शुरू हुआ था। इनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे यह संदेह भी पैदा हुआ है कि क्या देश में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे? नीतिगत स्थिरता का क्या होगा? शायद इसी संदेह की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। आशा है कि इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा, लेकिन नतीजों से यह भी तय है कि देश की राजनीति ने एक करवट ले ली है।

कच्चा तेल 4 डॉलर प्रति बैरल सस्ता

भारत के लिए इस मामले में शानदार मौका!

एजेंसी

ओपेक + कार्टेल द्वारा इस वर्ष उत्पादन में वृद्धि की अनुमति देने की योजना के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सप्ताह तेल की कीमतें 4 डॉलर प्रति बैरल से अधिक गिरकर चार महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं, जबकि अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में वृद्धि ने मंदी की भावनाओं को और बढ़ा दिया है। इसका फायदा भारत को होने की पूरी गुंजाइश है। IANS की खबर के मुताबिक, अगस्त के लिए बेंचमार्क ब्रेंट ऑयल वायदा बुधवार को 77.50 डॉलर पर आ गया, जबकि डब्ल्यूटीआई (वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट) पर जुलाई के कच्चे तेल के वायदे 73.22 डॉलर पर थे।

कीमतें अब 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे

खबर के मुताबिक, 7 फरवरी के बाद पहली बार तेल की कीमतें अब 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है और तेल की कीमतों में किसी भी गिरावट से देश के आयात बिल में कमी आती है। इससे चालू खाता घाटा (सीएडी) कम होता है और रुपया मजबूत होता है। बाहरी संतुलन को मजबूत करने के अलावा, तेल की कीमतों में गिरावट से घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें भी कम होती हैं जिससे देश में मुद्रास्फीति कम होती है।

रूस अब भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर

सरकार ने यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर पश्चिमी दबाव के बावजूद तेल कंपनियों को रियायती कीमतों पर रूसी कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देकर देश के तेल आयात बिल को कम करने में भी मदद की है। नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका और यूरोप द्वारा मास्को के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने में दृढ़ रही है। रूस अब भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है, जिसने पहले इराक और सऊदी अरब की जगह ली थी, जो पहले शीर्ष स्थान पर थे। भारत वास्तव में रूस के समुद्री तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है, जो अप्रैल में भारत के कुल तेल आयात का लगभग 38 प्रतिशत था।

देश के तेल आयात बिल में बड़ा बचत

आईसीआरए की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस से तेल आयात की कीमत वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के 11 महीनों में खाड़ी देशों से इसी स्तर की तुलना में क्रमशः 16.4 प्रतिशत और 15.6 प्रतिशत कम थी। रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखने की भारत की रणनीति के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों के दौरान देश के तेल आयात बिल में लगभग 7.9 बिलियन डॉलर की बचत हुई है और देश को अपने चालू खाता घाटे को कम करने में भी मदद मिली है। चूंकि भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, इसलिए रूसी तेल की इन बड़ी खरीदों ने विश्व बाजार में कीमतों को अधिक उचित स्तर पर रखने में भी मदद की है, जिसका लाभ अन्य देशों को भी मिला है।

बदले हालात में मोदी का सत्ता में आना सुधारों को चुनौतीपूर्ण बनाएगा, जानें अर्थशास्त्रियों ने और क्या कहा

नई दिल्ली। एजेंसी

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद नई सरकार बनने पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदले हुए सियासी हालात में सत्ता में अगर लौटते हैं तब महत्वपूर्ण सुधारों के अमल में ला पाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अर्थशास्त्रियों ने चुनावी नतीजों के बाद यह राय जताई। भाषा की खबर के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, लोकसभा चुनावों की मतगणना के नतीजों से यह सामने आया कि मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) तो बहुमत में आ गई है, लेकिन भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से पीछे रह गई।

आर्थिक नीति की व्यापक दिशा में बदलाव की संभावना नहीं

खबर के मुताबिक अर्थशास्त्रियों ने इसे एक नकारात्मक आश्चर्य बताया। घरेलू ब्रोकरेज फर्म एम्के ने एक टिप्पणी में कहा कि इस बात की संभावना है कि नरेन्द्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में वापस आएंगे। हालांकि उन्हें शासन में बदली हुई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। टिप्पणी में आगे कहा गया कि इस तरह की स्थिति में आर्थिक नीति की व्यापक दिशा में बदलाव की संभावना नहीं है।

स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस के विश्लेषको ने उम्मीद जताई कि नई सरकार विनिर्माण, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने, श्रम सुधारों को लागू करने, कौशल विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने सहित आपूर्ति-पक्ष के सुधारों को आगे बढ़ाने का काम करेगी।

कई सुधारों को लागू करना

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि हालांकि हमें लगता है कि भूमि सुधार, बुनियादी ढांचे पर खर्च को बढ़ावा देना, विनिवेश, कृषि विधेयक, समान नागरिक संहिता और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने जैसे कठोर सुधारों को लागू करना इस सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। आरबीएल बैंक की अचला जेठमलानी ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को मामूली अंतर से मिली जीत जरूरी सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा सकती है, जिससे भारत की वृद्धि गाथा को समर्थन मिलेगा। एम्के ने कहा कि सरकार के लिए तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भरता होने से उनके हिसाब से नीतियों को समायोजित करना होगा।

Opec+ की कटौती से नहीं बिगड़ेगी तेल आपूर्ति, मंत्रालय के अधिकारियों को कीमतों में भी कमी रहने की उम्मीद

एजेंसी

ओपेक प्लस देशों द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन मौजूदा स्तर पर जारी रखे जाने से भारत की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका नहीं है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि वैश्विक औद्योगिक मांग कम रहने और रूस के कच्चे तेल पर छूट जारी रहने की स्थिति में भारत की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी।

रविवार को ओपेक प्लस देशों ने उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती की अवधि आगे बढ़ाने का फैसला किया था। इस समूह ने उत्पादन में कुल 58.6 लाख बैरल प्रतिदिन या तेल की वैश्विक मांग का 5.7 प्रतिशत कटौती जारी रखने की घोषणा की है। इसमें प्रमुख उत्पादन में 36.6 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती 2025 के अंत तक किया जाना शामिल है। साथ ही सऊदी अरब और रूस सहित 8 देशों द्वारा वर्तमान में लागू की जा रही 22 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन में कटौती को भी 3 महीने के लिए सितंबर के अंत तक बढ़ा दिया जाएगा। कटौती की यह योजनाएं जून के अंत तक खत्म होने वाली थीं, लेकिन अब इसे अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

एक अधिकारी ने कहा, 'ताजा घोषणा उत्पादन में मौजूदा कटौती को जारी रखने की है। इससे भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।' अधिकारियों ने कहा कि ढुलाई की लागत बढ़ने और जहाजों की लूट के जोखिम से भारत को तेल की आपूर्ति बाधित होने से अस्थायी रूप से तेल के दाम में उतार चढ़ाव हो सकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'हम लाल सागर और फारस की खाड़ी में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। 2022 से भू राजनीतिक जोखिम बार बार बढ़ने से इस क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्ग बाधित हुए हैं। अब तक भारत का आयात बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति लगातार गतिशील बनी हुई है।' कच्चे तेल की वैश्विक मांग में गिरावट की चिंता से तेल उत्पादक देशों की चिंता बढ़ी है। ओपेक ने 2024 के आखिरी महीनों में तेल की मांग बढ़ने का अनुमान लगाया है, वहीं मांग में वृद्धि को लेकर स्थिति निश्चित है।

चीन सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल महीने में चीन के कच्चे तेल का उत्पादन 3.3 प्रतिशत घटकर 143.6 लाख बैरल प्रति दिन रह गया, जो अगस्त 2022 के बाद सालाना आधार पर पहली मासिक गिरावट है। अधिकारियों को उम्मीद है कि कम मांग के कारण कीमतों में कमी रहेगी। अप्रैल की शुरुआत में कई बार 90 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बाद ब्रेंट क्रूड अब मई में 81-82 डॉलर के स्तर पर स्थिर हो गया है। ओपेक प्लस की घोषणा के बाद कीमत 80.75 डॉलर के स्तर पर स्थिर है और यह सोमवार को रिपोर्ट लिखे जाने के वक्त 80.8 डॉलर प्रति बैरल थी।

बहरहाल अधिकारियों ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता से ओपेक को आगे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ सकता है और आगे अगर और कटौती होती है तो इससे आपूर्ति का संतुलन प्रभावित हो सकता है। ओपेक ने 2024 तेल के वैश्विक मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया था। मार्च से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और 22 लाख बैरल प्रतिदिन बना हुआ है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि भारत के तेलशोधकों को छूट पर रूस से लगातार तेल मिलते रहने का आश्वासन मिला है। एक सरकारी रिफाइनरी के अधिकारी ने कहा, 'रूस के तेल पर छूट 2023 के मध्य में कम हो गई थी, लेकिन बाद के महीनों में फिर छूट मिलने लगी। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए इस बात के कोई संकेत नहीं हैं, कि छूट में अचानक कोई भारी कमी कर दी जाएगी।' वैश्विक ट्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म केप्लर के अनुमान के मुताबिक मई तक भारत के कुल आयात में रूस के कच्चे तेल की हिस्सेदारी 40.9 प्रतिशत बनी हुई है, जो 42 प्रतिशत के ऐतिहासिक उच्च स्तर की तुलना में थोड़ा कम है।

2000 रुपये के 97.82 प्रतिशत नोट आ गए वापस, अभी भी 7,755 करोड़ रुपये मूल्य के नोट लोगों के पास

एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि दो हजार रुपये मूल्य के 97.82 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गये हैं। चलन से हटाये गये केवल 7,755 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अभी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। चलन में 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था। यह 31 मई, 2024 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 7,755 करोड़ रुपये रह गया। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, "इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक चलन में 2000 रुपये के 97.82 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गये हैं।"

7 अक्टूबर, 2023 तक सभी बैंकों में बदले गए नोट

सात अक्टूबर, 2023 तक 2000 रुपये के बैंक नोट को जमा करने और/या बदलने की सुविधा देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। उन्नीस मई, 2023 से 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई के निर्गम कार्यालय नौ अक्टूबर, 2023 से व्यक्तियों और संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 रुपये के नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, लोग अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए देश के किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपये के बैंक नोट भेज रहे हैं।

RBI के इन कार्यालयों में बदले जा रहे 2000 के नोट

बैंक नोट को जमा/बदलने वाले आरबीआई के 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं। उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2016 में उस समय चलन में मौजूदा 1000 रुपये और 500 रुपये के बैंक नोट को हटाये जाने के बाद 2000 रुपये के बैंक नोट लाये गये थे।

स्वास्थ्य बीमा को सुलभ और किफायती बनाएगा मासिक प्रीमियम, इस तरह उठाएं फायदा

एजेंसी

क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं, जो सही स्वास्थ्य बीमा योजना चुनना चाहते हैं, लेकिन प्रीमियम की कीमतों को लेकर झिझक रहे हैं? खैर, ऐसे आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं! सही स्वास्थ्य बीमा योजना ढूंढ़ना भारी पड़ सकता है, क्योंकि लागतों को नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो सकता है। कोई आश्चर्य नहीं, भारत में तीन में से केवल एक व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शामिल हैं। लेकिन क्या होगा, अगर आपको पता चले कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करना अब आपके मासिक ओटीटी या किराने की खरीदारी जितना आसान हो सकता है?

स्वास्थ्य बीमा, एक खर्च या एक निवेश?

भारत में स्वास्थ्य बीमा को हमेशा किसी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा जाल के बजाय, आर्थिक भार के रूप में देखा जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय लगभग 16 हजार रुपये प्रति माह है। स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, जब सालाना देय होता है, तो एक महीने के वेतन का लगभग 30 प्रतिशत (प्रीमियम के रूप में 5,000 रुपये मानकर) होता है। इससे एक बार में भुगतान करना मुश्किल हो जाता है।

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी एक भयावह तस्वीर पेश करती है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि इस तरह के खर्चों के कारण हर साल 55 मिलियन भारतीय गरीबी में वापस चले जाते हैं। यह परिदृश्य सुरक्षा जाल की बढ़ती ज़रूरत को दर्शाता है। लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि स्वास्थ्य बीमा एक विलासिता नहीं, बल्कि उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

मासिक प्रीमियम योजनाएं जेब पर हल्की

फोनपे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के बिजनेस हेड, नीलेश अग्रवाल कहते हैं कि मासिक प्रीमियम योजनाएं जेब पर हल्की होती हैं और उपयोगकर्ताओं को उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं। सभी आय वर्गों में बीमा उत्पादों की पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने की इस जरूरत को समझने के बाद, फोनपे ने बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए अपनी तरह की पहली मासिक सदस्यता शुरू की। इसमें भुगतान विकल्प 500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति माह तक है।

जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करता है

यह सुविधा स्वास्थ्य बीमा को सालाना एकमुश्त भुगतान के बोझ से दबने के बजाय अपने आवर्ती मासिक घरेलू बिलों का भुगतान करना जितना आसान बनाती है। यह आपकी जेब पर भी आसान है, भुगतान करने में सुविधाजनक है, और वास्तव में हमारी मूल विचारधारा -- बीमा आपके तरीके से -- के साथ प्रतिध्वनित होता है। मासिक प्रीमियम भुगतान योजनाएं स्वास्थ्य बीमा श्रेणी में उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से आधुनिक भारतीय उपभोक्ता के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार करने में मदद कर सकती हैं।

देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ

एजेंसी

देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में 3,288.52 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) के औसत खाद्यान्न उत्पादन 3,077.52 लाख टन से 211 लाख टन अधिक है। कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को तीसरे अग्रिम अनुमान में बताया कि हालांकि 2022-23 की तुलना उत्पादन में मामूली कमी आई है। मंत्रालय ने 2023-24 में अनियमित मानसून को अनाज उत्पादन में गिरावट का कारण बताया है जिससे कुछ फसलें प्रभावित हुई थीं। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, यह तथ्य कि कुल उत्पादन पांच साल के औसत से अधिक है, देश के कृषि क्षेत्र में लचीलापन दर्शाता है।

चावल-गेहूं का उत्पादन बढ़ा

तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2023-24 में कुल चावल उत्पादन 1,367.00 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 में यह 1,357.55 लाख टन था। गेहूं का उत्पादन 1,129.25 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के इसी आंकड़े की तुलना में 23.71 लाख टन अधिक है। श्री अन्न (बाजरा) का उत्पादन 174.08 लाख टन होने का अनुमान है, जो 2022-23 की तुलना में 87 हजार टन की मामूली वृद्धि को दर्शाता है।

दलहनों का उत्पादन बढ़ा

वर्ष के दौरान दलहनों का उत्पादन बढ़ा है। तुअर का उत्पादन 33.85 लाख टन अनुमानित है, जो 2022-23 में 33.12 लाख टन की तुलना में 0.73 लाख टन अधिक है। मसूर का उत्पादन 17.54 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 15.59 लाख टन की तुलना में 1.95 लाख टन अधिक है। सोयाबीन का उत्पादन 130.54 लाख टन, और रेपसीड तथा सरसों का उत्पादन 131.61 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 5.18 लाख टन अधिक है। आंकड़ों के अनुसार, कपास का उत्पादन 325.22 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) और गन्ने का उत्पादन 4425.22 लाख टन होने का अनुमान है।

तूफानी तेजी पर बंद हुआ शेयर बाजार... 2300 अंक चढ़ा सेंसेक्स

झटके में 13 लाख करोड़ की कमाई

मुंबई। एजेंसी

बुधवार को बीएसई सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। सभी शेयरों में शानदार तेजी रही. सबसे ज्यादा तेजी इंडसइंड बैंक में 7.75 फीसदी की रही। इसके बाद टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में 7 फीसदी की रही। मंगलवार को भंयकर गिरावट के बाद शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखी गई। बीएसई एहीं बुधवार को 2300 अंक चढ़कर 74,382.24 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 735.85 अंक चढ़कर 22,620.35 पर बंद हुआ. वहीं बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी रही। यह 2,126 अंक चढ़कर 49,054 लेवल पर बंद हुआ। इसके अलावा, मिडकैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी धुंआधार तेजी रही। बुधवार को बीएसई सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। सभी शेयरों में शानदार तेजी रही। सबसे ज्यादा तेजी इंडसइंड बैंक में 7.75 फीसदी की रही। इसके बाद टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक में 7 फीसदी की रही। सबसे कम उछाल एल एंड टी के शेयरों में सिर्फ 0.20 फीसदी की रही।

74 स्टॉक ने लगाया अपर सर्किट

एनएसई के 2,771 शेयरों में से बुधवार को 1,956 शेयरों में उछाल रही, जबकि 721 शेयरों में गिरावट आई। 94 शेयर अनचेंज रहे. 69 शेयर 52 सप्ताह के हाई लेवल पर कारोबार कर रहे थे, जबकि 89 शेयर 52 सप्ताह के लो लेवल पर थे। 74 शेयरों में अपर सर्किट रहा जबकि 267 शेयरों में लोअर सर्किट रहा।

निवेशकों की 13 लाख करोड की कमाई

भारी गिरावट के बाद जब आज मार्केट ओपन हुआ तो धुआंधार तेजी आई और सेंसेक्स के साथ ही इसका मार्केट कैप भी तेजी से चढ़ा बीएसई का मार्केट कैप एक बार फिर 400 लाख करोड़ के पार चला गया। मंगलवार की तुलना में बुधवार को बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 407.8 लाख करोड़ रुपये हो गया।

इन 10 शेयरों में शानदार तेजी

अडानी ग्रीन एनर्जी शेयर 11.11 फीसदी चढ़कर 1,828 रुपये पर पहुंच गया। Adani Port के शेयर में 8.45 फीसदी की तेजी आई। इसके अलावा ट्रेंट में 8 फीसदी आदित्य बिरला फैशन रिटेल में 15 फीसदी की तेजी रही। वोडाफोन आइडिया के शेयर 12 फीसदी, व्हें ल्यूात के शेयर 10 फीसदी, ज्योति लैब्स 13.64 फीसदी, अमरा राजा एनर्जी में 12.48 फीसदी, NALCO के शेयर 11 फीसदी, चंबल फर्टिलाइजर 11 फीसदी और ऐंथ्ड के स्टॉक में 10 फीसदी की तेजी आई।

सरकार ने कच्चे तेल पर घटाया विंडफॉल टैक्स, इन कंपनियों को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाकर शनिवार से 5,200 रुपये प्रति टन कर दिया। यह पहले 5,700 रुपये प्रति टन था। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि नई दर 1 जून से लागू होगी। विंडफॉल टैक्स कम होने का सीधा फायदा घरेलू स्तर पर कच्चा तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को मिलता है। पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर विंडफॉल टैक्स शून्य बना हुआ है।

15 दिन में समीक्षा की जाती है टैक्स की- सरकार द्वारा हर 15 दिन में कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की समीक्षा की जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर ही विंडफॉल टैक्स को घटाया या बढ़ाया जाता है। पिछले कुछ महीनों में सरकार की ओर से कई बार विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है। इससे पहले 16 मई को सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 8,400 रुपये से घटाकर 5,700 रुपये प्रति टन कर दिया था। वहीं, 1 मई को इसे 9,600 रुपये से घटाकर 8,400 रुपये प्रति टन कर किया गया था।

1 जुलाई 2023 से विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू हुआ था- कच्चे तेल की कीमत अचानक बढ़ने के कारण तेल कंपनियों को हो रहे अप्रत्याशित मुनाफे पर सरकार ने 1 जुलाई 2023 से विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू किया था। कच्चे तेल के साथ, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर भी विंडफॉल टैक्स लगाया गया है। विंडफॉल टैक्स लाने की एक वजह निजी तेल रिफाइनरियों को नियंत्रित करना था, जो अच्छे मार्जिन के कारण घरेलू बाजार में आपूर्ति को दरकिनार कर विदेशों में तेल निर्यात कर रही थीं।

मई 2024 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.73 लाख करोड़ रूपये, वर्ष-दर-वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई

एजेंसी

मई 2024 के महीने के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.73 लाख करोड़ रुपये रहा। इसमें वर्ष-दर-वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जो घरेलू लेनदेन में मजबूत वृद्धि (15.3 प्रतिशत वृद्धि) और आयात में कमी (4.3 प्रतिशत) दर्शाता है। रिफंड के बाद, मई 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.44 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में मई 2024 तक सकल जीएसटी संग्रह 3.83 लाख करोड़ रुपये रहा। यह वर्ष-दर-वर्ष 11.3 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है, जो घरेलू लेनदेन में मजबूत वृद्धि (14.2 प्रतिशत) और आयात में मामूली वृद्धि (1.4 प्रतिशत) से संभव हुआ है। रिफंड के बाद, वित्त वर्ष 2024-25 में मई 2024 तक शुद्ध जीएसटी राजस्व 3.36 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अंतर-सरकारी समझौताः

मई, 2024 के महीने में केंद्र सरकार ने 67,204 करोड़ रुपये के शुद्ध आईजीएसटी से सीजीएसटी को 38,519 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 32,733 करोड़ रुपये का निपटान किया। नियमित निपटान के बाद, मई, 2024 में सीजीएसटी के लिए कुल राजस्व 70,928 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 72,999 करोड़ रुपये हो गया।

इसी तरह, वित्त वर्ष 2024-25 में मई 2024 तक केंद्र सरकार ने 1,54,671 करोड़ रुपये के शुद्ध आईजीएसटी संग्रह से सीजीएसटी को 88,827 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 74,333 करोड़ रुपये का निपटान किया। निपटान के बाद, वित्त वर्ष 2024-25 में मई 2024 तक सीजीएसटी के लिए 1,65,081 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 1,68,137 करोड़ रुपये का कुल राजस्व है।

जीपीओ परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

इंदौर जीपीओ परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुश्री प्रीती अग्रवाल पोस्टमास्टर जनरल, इंदौर परिक्षेत्र के द्वारा पौधारोपण करते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सन्देश दिया गया । इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अधिकारी व स्टाफ़ ने भी पौधारोपण में सक्रियता से भाग लिया। सुश्री प्रीती अग्रवाल द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि लगातार बढ़ते तापमान और वृक्षों की लगातार कटाई के कारण प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है । प्रकृति की संरक्षा के उद्देश्य से सभी को अपना योगदान देना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए । पर्यावरण की रक्षा मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है । वर्ष 2024 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 'हमारी भूमि' के नारे के तहत भूमि बहाली,

मरुस्थलीकरण और सूखे पर केन्द्रित है । अतः उनके द्वारा इस दिवस पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया एवं प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने हेतु प्रेरित किया गया । विश्व पर्यावरण के पर्व पर इंदौर परिक्षेत्र के अन्तर्गत समस्त 17 ज़िलों के डाक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी प्रत्येक डाक घर में पौधारोपण के निर्देश जारी किए गए हैं । यह पर्यावरण संरक्षा हेतु इंदौर डाक परिवार का छोटा सा प्रयास है। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक डाकघर इंदौर नगर संभाग, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के वरिष्ठ अधिकारीगण, इंदौर नगर मंडल एवं मोफसिल संभाग के अधिकारीगण, वरिष्ठ पोस्टमास्टर इंदौर जीपीओ तथा समस्त कर्मचारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे ।

रिजर्व बैंक के आंकड़ें बता रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड बढ़ गया 708 प्रतिशत तो बैंक फ्रॉड 300 प्रतिशत, जानिए पूरी बात

मुंबई। एजेंसी

आप खबरों पर नजर डालते होंगे तो देखते होंगे कि हर रोज अखबारें में डिजिटल फ्रॉड या धोखाधड़ी की खबर छपती ही रहती है। इस बात की तस्दीक भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी करती है। जी हां, कल ही रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इससे पता चलत है कि दो साल के दौरान डिजिटल फ्रॉड की घटनाओं में 708 फीसदी तो बैंक फ्रॉड की घटना में 300 फीसदी की तेज बढ़ोतरी हुई है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान बैंक फ्रॉड की घटना में काफी इजाफा हुआ है। इस साल रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 36,075 थी, जो वित्त वर्ष 2021-22 में रिपोर्ट किए गए 9,046 मामलों से लगभग 300 फीसदी अधिक है। हालांकि, इसमें शामिल राशि 45,358 करोड़ रुपये से गिरकर 13,930 करोड़ रुपये हो गई है। राशि के हिसाब से देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी में शामिल राशि में 46.7 प्रतिशत की गिरावट आई।

सरकारी या प्राइवेट बैंक, कहां हुए ज्यादा फ्रॉड

आरबीआई ने नोट किया कि

जहां निजी क्षेत्र के बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में धोखाधड़ी की सबसे अधिक संख्या की सूचना दी, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी की राशि में अधिकतम योगदान दिया। रिजर्व बैंक ने बताया कि संख्या के लिहाज से धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान (कार्ड भुगतान और इंटरनेट) में हुई। हालांकि, मूल्य के संदर्भ में, धोखाधड़ी मुख्य रूप से लोन पोर्टफोलियो में दर्ज की गई थी। आरबीआई के विश्लेषण से पता चला, 'जहां निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या में छोटे मूल्य के कार्ड/ इंटरनेट धोखाधड़ी ने अधिकतम योगदान दिया, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी मुख्य रूप से लोन पोर्टफोलियो में थी।'

डिजिटल पेमेंट के फ्रॉड में भारी बढ़ोतरी

कार्ड और इंटरनेट भुगतान से संबंधित फ्रॉड की संख्या तो तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2021-22 में ऐसी धोखाधड़ी की संख्या 3,596 थी जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 29,082 हो गई। मतलब 708 फीसदी की भारी बढ़ोतरी। मूल्य के संदर्भ में भी यह 155 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,457 रुपये हो गया।

फ्रॉड का पता चलने में दरी

FY23 और FY24 के दौरान रिपोर्ट किए गए मामलों पर किए गए एक अध्ययन में RBI ने धोखाधड़ी की घटना की तारीख और उसका पता चलने के दिन के बीच 'महत्वपूर्ण' समय अंतराल देखा। आरबीआई ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्षों में हुई धोखाधड़ी में शामिल राशि, मूल्य के संदर्भ में वित्त वर्ष 2023 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का 94.0 प्रतिशत थी। मूल्य के हिसाब से वित्त वर्ष 2024 में रिपोर्ट की गई लगभग 89 प्रतिशत धोखाधड़ी पिछले वित्त वर्ष में हुई थीं। मतलब कि लोगों को बाद में पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है।

//

Fitch ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में नहीं किया बदलाव, 'BBB-' को रखा बरकरार

एजेंसी

लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद फिच रेटिंग (Fitch Ratings) ने भारत के लिए क्रेडिट रेटिंग जारी की है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। भारत के लिए रेटिंग आउटलुक भी स्थिर बना हुआ है।

भारत को मिली BBB- रेटिंग

CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, फिच रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी माइनस (BBB-) पर बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी ने बुधवार को जानकारी दी कि फिलहाल आग के लिए संकेत ठीक हैं। फिच ने कहा कि CAPEX को बढ़ावा देने का रुख जारी रह सकता है। इसके अलावा, रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सरकार का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर रह सकता है।

क्या है भारत को मिलने वाली BBB- रेटिंग का मतलब?

क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि किसी देश की कर्ज को वापस चुकाने की कितनी क्षमता है। इसके ही आधार पर उस देश को लोन मिलने में आसानी या मुश्किलें आती हैं। हर कैटेगरी में प्लस और माइनस रेटिंग दी जाती है। ट्रिपल बी में माइनस मिलने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जोखिम। इसके नीचे डबल बी (BB) कैटेगरी आती है जिसका मतलब डिफॉल्ट का जोखिम ज्यादा होने से होता है। वहीं, ट्रिपल ए (AAA) में सबसे कम जोखिम होता है और डी कैटेगरी में कमिटमेंट पर डिफॉल्ट होने वाले शामिल किए जाते हैं। फिच रेटिंग कुल 11 कैटेगरी में रेटिंग देता है।

फिच ने बढ़ाया था भारत के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान

फिच रेटिंग्स ने 14 मार्च को भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष 2025 के लिए बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इसके पहले के अनुमान में एजेंसी ने 6.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था। रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'कारोबारियों और ग्राहकों का भरोसा टिकाऊ स्तर पर बरकरार रहने के बीच घरेलू मांग, खासकर निवेश अर्थव्यवस्था की वृद्धि का मुख्य चालक होगा। हमारे अनुमान के मुताबिक कम अवधि के हिसाब से वृद्धि, अर्थव्यवस्था की अनुमानित क्षमता को पीछे छोड़ देगी। ऐसे में वित्त वर्ष 2025 में वृद्धि दर में सुधार होगा।'

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को यह भी उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में वृद्धि 7.8 प्रतिशत रहेगी, जो सरकार के 7.6 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान से थोड़ा अधिक है।

S&P ने भारत के लिए नजरिया 'स्थिर' से बढ़ाकर 'पॉजिटिव' किया

एसएेंडपी (S&P) ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरिन रेटिंग बीबीबी- और अल्पकालिक रेटिंग ए-3 ही रखी है। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि का इसकी साख पर अच्छा असर हो रहा है। हमें उम्मीद है कि मजबूत आर्थिक बुनियादी कारकों के दम पर अगले दो से तीन साल तक वृद्धि की रफ्तार बनी रहेगी।' मगर एजेंसी ने कहा है कि अगर सार्वजनिक वित्त को टिकाऊ बनाए रखने का राजनीतिक संकल्प डगमगाया तो वह अपना नजरिया वापस स्टेबल पर ले आएगी। उसका कहना है कि राजनीतिक संकल्प घटा तो देश की संस्थागत क्षमताएं भी कमजोर हो जाएंगी। एसएेंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा, 'पॉजिटिव नजरिया देने की वजह हमारा यह मानना है कि नीतियों में स्थिरता बनी रहने, आर्थिक सुधारों की पैठ गहरी होने और संस्थागत निवेश ऊंचा रहने से वृद्धि की दीर्घकालिक संभावनाएं बनी रहेंगी।'

GMR के नेतृत्व में दिल्ली एयरपोर्ट का कमाल, प्रति यात्री बिजली खपत में की 57प्रतिशत की कमी

नई दिल्ली। एजेंसी

जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के नेतृत्व में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने बिजली खपत को कम करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एयरपोर्ट ने साल 2010 से प्रति यात्री बिजली की खपत में 57 फीसदी की कमी की है। इसका लक्ष्य साल 2030 तक नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट बनना है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है। साल 2010 में जब टर्मिनल-3 चालू हुआ था, प्रति यात्री बिजली खपत 5.18 kWh थी। विभिन्न ग्रीन इनिशिएटिव को लागू करने से DIAL ने इस आंकड़े को साल 2023 में घटाकर 2.21 kWh कर दिया।

ये उठाए हैं कदम

DIAL के CEO विदेह कुमार जयपुरिया ने कहा, 'DIAL का आगे फोकस इनोवेटिव सॉल्यूशंस को लागू करने और बेहतर तरीकों का लाभ उठाकर सर्विस क्वालिटी और पैसेंजर कंफर्ट के हायर स्टैंडर्ड को बनाए रखते हुए विशिष्ट ऊर्जा खपत में साल-दर-साल कमी लाने पर है।' DIAL के एनर्जी सेविंग मेजर्स में ग्रीन बुइल्डिंग प्रेक्टिसेस को शामिल करना, एनर्जी एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करना और खपत को और कम करने के लिए निरंतर प्रयास शामिल हैं। इसमें हवाई अड्डे की जटिल प्रणालियों जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC), बैगेज हैंडलिंग सिस्टम (BHS), सूचना प्रौद्योगिकी (IT), एयरसाइड ग्राउंड लाइट (AGL) में स्वचालन का उपयोग, एलईडी लाइटों का उपयोग और वास्तविक समय की निगरानी और नियंत्रण के माध्यम से एसेट परफॉर्मेंस को अधिकतम करने व ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए VHT प्रणाली शामिल है।

100 प्रतिशत बिजली जरूरत रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करता है एयरपोर्ट

दिल्ली हवाई अड्डा अपनी 100 प्रतिशत बिजली जरूरतों को नवीकरणीय स्त्रोतों यानी सौर और जल विद्युत से पूरा करता है। ने एयरसाइड पर एक 7.45 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जो किसी भारतीय हवाई अड्डे पर एयरसाइड पर इस तरह का पहला प्लांट भी है। भविष्य में बिजली की खपत को और कम करने की योजना बना रहा है। इसमें नए टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेलाइट हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को अपनाना, एडवांस्ड बीएचएस प्रणाली की स्थापना और प्रणाली में 100 प्रतिशत एलईडी लाइट्स शामिल हैं।

IATA ने GST शुल्क पर विदेशी एयरलाइनों के खिलाफ जांच पर जताई चिंता

दुबई। एजेंसी

वैश्विक एयरलाइन समूह आईएटीए ने एक भारतीय एजेंसी द्वारा कुछ विदेशी एयरलाइनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित कुछ शुल्कों की जांच को लेकर मंगलवार को चिंता जाहिर की। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने भारत में परिचालन करने वाली कुछ विदेशी एयरलाइन के खिलाफ जांच शुरू कर है। आईएटीए के भारत के 'कंट्री डायरेक्टर' अमिताभ खोसला ने यहां कहा कि फिलहाल 10 विदेशी एयरलाइन के खिलाफ जांच की जा रही है और यह कदम 'अभूतपूर्व' है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) ने इस मुद्दे पर भारत सरकार को एक विस्तृत प्रतिवेदन दिया है। एयरलाइनों को अक्टूबर 2023 से नोटिस मिले हैं। उत्तर एशिया एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र (अंतरिम) के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शी शिंगक्वान ने भी आईएटीए की वार्षिक आम बैठक के दौरान आयोजित 'ब्रीफिंग' में जीएसटी मुद्दे का उल्लेख किया। बयान में कहा गया, "भारत में एयरलाइन के शाखा कार्यालय विमान पट्टे, चालक दल और पायलट, ईंधन तथा रखरखाव लागत के लिए अनुबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। भारत से आने-जाने वाले सभी परिचालनों का निर्णय, नियंत्रण और संचालन एयरलाइनों के मुख्य कार्यालयों द्वारा लिया जाता है। भारत में शाखा कार्यालयों को किसी भी रणनीतिक और/या परिचालन जोखिम तथा कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना कानूनी रूप से सही नहीं है।" भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। आईएटीए 330 से अधिक एयरलाइन का समूह है, जो वैश्विक हवाई यातायात का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संभालता है।

विश्व पर्यावरण दिवस के उद्देश्य को म.प्र. में सार्थक करेगा ''नमामि गंगे'' अभियान

''विश्व पर्यावरण दिवस'' वर्ष 1972 में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जागरूक करने के लिए ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संवेदना को बढ़ावा देना है। वैसे तो पर्यावरण एक दिन कार्यक्रम करने का विषय नहीं है, यह एक संकल्प है जो निरन्तर चलने वाली सुधारात्मक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। 5 जून एक ऐसा अलार्म है जो हमें पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करता है। इस दिन लोग पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने और इसके संरक्षण के लिए समेकित स्वर में आवाज उठाते हैं।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए सतत रूप से कार्य किये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन पर्यावरण प्रेमी होने के साथ पर्यावरण के इको सिस्टम के प्रति संवेदनशील भी है। पर्यावरण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में पर्यावरण सचेतना कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूल-कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं। आज के युवा पर्यावरण के प्रति सजग और समर्पित है। आज के समय की एक और मांग है कि वृक्षों का स्थानांतरण - यानी ट्री ट्रांसप्लांट करना। इसके बारे के जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। अक्सर देखा गया है कि निर्माण कार्यों में पेड़ों को काट दिया जाता है जबकि उन्हें ट्रांसप्लांट कर बचाया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह कार्य बहुत जटिल भी नहीं है। अन्य राज्यों की अपेक्षा मध्यप्रदेश में जंगलों एवं वृक्षों की संख्या अच्छी है लेकिन हमें इसे समय की जरूरत को देखते हुए और बढ़ाना है। ट्री ट्रांसप्लांट से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए जल संरक्षण अभियान और जल संचारण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। शहरों में ''रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'' को बढ़ावा देने के लिए नियम में स्पष्टता लाई जा रही है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में स्टॉप डेम, खेत तालाब, सिंचाई की आधुनिक पद्धति ड्रिप इरीगेशन जिसमें जल को कल के लिए बचाया जा सके, इस दिशा में काम चल रहा है। म.प्र. में 'झी ऊ्दज स्दी म्ेदज' की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण युवा जल संरक्षण को लेकर बहुत जागरूक दिखाई दे रहे हैं। स्वच्छता अभियान चलाकर शहरों और गाँवों को स्वच्छ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कचरा निस्तारण किया जा रहा है। शहरों में तो दिन और रात सफाई हो रही हैं। इंदौर भारत का पहला ऐसा शहर बना है जो स्वच्छता के 7 कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। वहीं कई गांव है जो आदर्श ग्राम बन कर प्रेरणा दे रहे हैं। बिजली और पानी की बचत के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उपायों पर काम किया जा रहा है। सुदूर क्षेत्रों में पेड़ लगाने और वन्यजीव संरक्षण के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए सामुदायिक संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करके एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण का संरक्षण करना है। जिससे आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस ले सके और शुद्ध हवा, शुद्ध जल आदि उनके लिए बचे रहे।

जैविक खेती आज की जरूरत है। किसान इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं लेकिन अभी और जागरूकता बाकी है। हम सब को मिलकर देशहित में प्रयास करना चाहिए कि जैविक खेती को अधिक से अधिक अपनाकर प्रेस्टीसाइड के उपयोग को कम किया जाए। इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण का तंत्र भी मजबूत होगा। आज के जमाने में हो रही बीमारियों में बहुत बड़ा कारण दवाई के छिड़काव से उत्पादित खेती का अनाज, सब्जी आदि का सेवन करना है। जबकि जैविक खेती न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि आर्थिक रूप से हमें सक्षम भी बनाती है। इतना ही नहीं जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण विषय है - गोवंश। गोवंश पालन आज की जरूरत है। गाय का हमारे जीवन में बहुत योगदान रहा है। गाय से सिर्फ दूध ही नहीं मिलता बल्कि उसके गोबर से 120 से ज्यादा उत्पाद बनाये जाते हैं। गाय के मूत्र से बनने वाला जीवामृत कृषि कार्य में उपयुक्त होने वाला सबसे बेहतरीन अमृत है। इसके उपयोग मात्र से फसलों में लगने वाली बीमारियां दूर हो जाती है। हमारी संस्कृति में गाय को माता माना गया है और उसकी पूजा की जाती है। गाय को गोधन भी इसलिए कहा जाता है कि वह हमारी संपदा भी है। उसके पालन से कई किसानों के परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अलसुबह गाय के दर्शन करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।

आज 5 जून से मध्य प्रदेश में ''नमामि गंगे'' अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान में तालाब, बावडी, पोखर, नदियों और अन्य जल स्त्रोतों का संरक्षण और पुनरुद्धार होगा, वहीं व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी भी इस दौरान की जाएगी। अभियान के दौरान जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराये जाएंगे। अभी वर्तमान में कुँए, बावड़ी और तालाब के गहरीकरण और उन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वहीं नदियों को उनका अस्तित्व लौटने के प्रयास जारी है।

जल संरचनाओं को व्यवसाय व रोजगार मूलक बनाने के उद्देश्य से पर्यटन, मत्स्य पालन, सिंघाड़े का उत्पादन जैसी संभावनाओं का निर्धारण किया गया है। चिन्हित जल संरचनाओं की मोबाइल ऐप से जियो टैगिंग भी की जाएगी। जल संग्रहण संरचना से निकाली गई मिट्टी एवं खाद का उपयोग स्थानीय कृषकों के खेतों में किए जाने को प्राथमिकता दी जायेगी। यह कार्य क्षेत्रीय जन सहयोग से और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जल संरचनाओं के किनारे पर यथा संभव बफर जोन तैयार किए जाएंगे। इस जोन में अतिक्रमण से बचाने एवं नदी तालाबों के कटावों को रोकने के लिए हरित क्षेत्र पार्क के विकास जैसे कार्य किए जाएंगे।

नगरीय क्षेत्र में जल संरचनाओं के जल की गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी। जन-जागरूकता के उद्देश्य से 6 जून को प्रत्येक नगरीय निकाय में जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 8 जून को जन भागीदारी से श्रमदान कर जल संरचनाओं की साफ-सफाई की जाएगी। 9 जून को जल संरचनाओं के समीप कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 9 जून को जल संरक्षण विषय पर निबंध, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय छात्र-छात्राएं सहभागिता करेंगे। 10 से 16 जून तक योजनानुसार जीर्णोद्धार के साथ-साथ जल संरचनाओं की साफ-सफाई भी होगी।

15 व 16 जून को ''गंगा दशमी'' के अवसर पर प्रमुख जल स्रोतों के किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत गंगा आरती, भजन समारोह इत्यादि आयोजित किये जायेंगें। जल स्त्रोतों के संरक्षण, जीर्णोद्धार व उन्नयन कार्यक्रम की निगरानी प्रतिदिन की जायेगी। इस अभियान के दौरान नगरीय क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

बढ़ता तापमान चिंता का विषय है। अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता और जन सहभागिता के साथ जल स्त्रोतों का संरक्षण और वृक्षारोपण होगा। जल स्त्रोतों, हाइवेज, प्रमुख मार्गो सहित पहाड़ियों में क्लस्टर प्लांटेशन किया जाएगा। ड्रिप इरीगेशन और फलदार वृक्षों का रोपण आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। इन्दौर संभाग में सभी ज़िलों में ऐसी जल संरचनाएं है जो प्राचीन समय के परोपकार की भावना को आज भी प्रदर्शित करती हैं। धार के मुंजसागर एवं देवी सागर सहित अन्य तालाबों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बुरहानपुर ज़िले में कुण्डी भंडारा के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे। माण्डू के जहाज महल एवं सागर तालाब के वॉटर मैंनजमेंट सिस्टम के जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा।

धार ज़िले में मनरेगा से बनी पुरानी जल संरचनाओं में व्यापक पैमाने पर मरम्मत और सुधार का कार्य किया जाएगा। बदनावर में 3 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। ज़िले में एक वॉट्सएप नंबर जारी किया गया है और विलुप्त हो रहे पोखरों, प्राचीन तालाबों और संकटग्रस्त नदियों की जानकारी ली जा रही है। नालछा और बाघिन नदी में भी कार्य किया जाएगा।

झाबुआ जिले में हमारी संस्कृति में पहाड़ों से लोक देवताओं का भी जुड़ाव है। ऐसे में हाथीपावा पहाड़ी के समान अन्य पहाड़ियों पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा और जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी के लिए कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। अनास नदी के संरक्षण के लिए दीर्घकालीन योजना बनायी जा रही है।

आलीराजपुर ज़िले में आम और नीम के पौधे विशेष तौर पर रोपे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 245 नये काम चिन्हित किए गए हैं। 05 जून को आलीराजपुर में जल सम्मेलन का आयोजन होगा, जहाँ पर धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को भी बुलाया जाएगा। सोंडवा में गेस्ट हाउस के सामने की पहाड़ी को पूरा हरा बनाने की मुहिम चलायी जाएगी।

खंडवा शहर में पद्म कुंड, रामेश्वर कुंड और सूरजकुंड की सफ़ाई और संरक्षण का काम होगा, वहीं नागचून तालाब की नहरों में हुए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। किशोर कुमार की समाधि के निकट स्टॉप डेम बनाया जाएगा। खरगोन ज़िले में बड़वाह और महेश्वर के बीच गंगा खेड़ी गाँव है। जनश्रुति है कि यहाँ पर गंगा माता भी गंगा दशहरा के दिन नर्मदा स्नान के लिए आती हैं। 16 जून को होने वाला प्रमुख कार्यक्रम यहाँ विशेष रूप से आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार धार जिले के मनावर तहसील में स्थित सातपयली में नर्मदा नदी में स्थिति गंगा कुंड के महत्व को भी रेखांकित किया जाएगा। बड़वानी जिले के अंजड़ में सरस्वती पहाड़ी में विशेष वृक्षारोपण किया जाएगा, वहीं जल संसाधन विभाग के समस्त तालाबों और अन्य कार्यों की रूपरेखा बना ली गई है।

इंदौर शहर सहित ज़िले के ग्रामीण अंचल में पुराने जल संरचनाओं में पानी आने के चैनल (स्त्रोतों) को सुधारा जाएगा। इंदौर शहर के विभिन्न तालाबों में पानी के चैनल पर हुए अतिक्रमण को सख़्ती से हटाने की कार्यवाही जारी है। कान्ह और सरस्वती नदी में निर्धारित दायरे में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने की तैयारी की जा रही है। 5 जून को इंदौर ज़िले के हर पंचायतों में होने वाले काम का चिन्हांकन कर लिया गया है। इंदौर ज़िले में जल हठ अभियान के तहत 56 तालाब चयनित किये गये हैं जहाँ पर काम किया जा रहा है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर तत्परता से जनसहयोग मिलता है। इंदौर एक शहर है जो कि पर्यावरण के मामले में अपने प्रयासों से मशहूर है। इंदौर ने कई पहल की हैं जो पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने के लिए की गई हैं। रालामण?डल, पितृ पर्वत इसके उदाहरण है।

इंदौर ने बाईक शेयरिंग और ई-रिक्शा परिचालन की शुरुआत की गई है। इंदौर ने वेस्ट टू आर्ट की दिशा में बेहतरीन काम करते हुए कई नवाचार किए। विश्राम बाग में करीब 21 टन स्क्रैप से अयोध्या के श्रीराम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की गई। 40 फीट लंबी और 27 फीट चौड़ी इस प्रतिकृति को देखने के निहारने के लिए कई देशों के लोग आ चुके हैं। इसके अलावा भी शहर में कई चौराहों को वेस्ट टू आर्ट के जरिए तैयार कलाकृतियों से सजाया गया।

सभी 19 जोन में श्री आर (रीड्यूज रीसाइकिल, रीयूजसेंटर) खोले। इन सेंटरों का उद्देश्य घरों में (पड़ी अनुपयोगी वस्तुओं, सामग्री को किसी के लिए उपयोगी बनाना है। इससे एक तरफ कचरा नियंत्रित करने में मदद मिली, वहीं दूसरी तरफ इस नवाचार से लोगों को काम भी मिला। शहरवासियों ने इन श्री आर सेंटरों को अच्छा प्रतिसाद दिया। अनुपयोगी इन वस्तुओं का उपयोग कर उपयोगी वस्तुएं तैयार की गईं।

इंदौर में सीएनजी बनाने की परिकल्पना के आधार पर गीले कचरे से बायो 'कूड़े से कमाई ' हेतु एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है। यह देश भर में अपनी तरह का पहला संयंत्र है जो कूड़े से कमाई की परिकल्पना पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इससे आबोहवा की हिफाजत के साथ ही सिटी बसों के ईंधन बिल में बड़ी कटौती भी हुई है। इस प्लांट में 500 टन गीले कचरे से 12 हजार किलो बायो सीएनजी प्रतिदिन तैयार हो रही है। निगम व निजी एजेंसियों के माध्यम से अभी प्रतिदिन करीब 500 वाहनों को बायो सीएनजी उपलब्ध करवाई जा रही है। गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाकर सिटी बसें व अन्य वाहन चलाने पर इंदौर को 'द बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनीशिएटिव' पुरस्कार मिला है।

इंदौर ने कई सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरु किया है जिससे शहर का प्रदूषण कम हो रहा है। इन सभी पहलों के माध्यम से इंदौर ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है और दूसरे शहरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल स्थापित की है। इंदौर जिले में नगर निगम द्वारा 'मैं हु झोलाधारी अभियान' चालू किया गया है, जिसमें रहवासियों को कपड़े की थैलियां वितरित की जा रही हैं एवं प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग ना करने की सलाह दी जा रही है।

United Nations के 17 Sustainable Development Goals में से SDG 6 - Clean water and sanitation (स्वच्छ जल और स्वच्छता), SDG 10 - Reduced inequalities (असमानताओं में कमी), SDG 11 - Sustainable cities and communities (टिकाऊ शहर और समुदाय), SDG 13 - Climate action (जलवायु कार्रवाई), SDG - 14 Life below water (पानी के नीचे जीवन), SDG -15 Life on land (भूमि पर जीवन), SDG 17 - Partnerships for the goals (लक्ष्यों के लिए साझेदारी) जैसे वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में ''नमामि गंगे'' अभियान योगदान कर सकेगा।

श्री दीपक सिंह
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं वर्तमान में इंदौर के संभागायुक्त हैं।

धन समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए शनिवार को करें ये खास टोटके, मिलेगा भरपूर लाभ

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से मिडिल क्लास वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खर्चे हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी के जरिया कम होता जा रहा है, इसकी वजह से कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तंत्र शास्त्र में धन समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ खास टोटकों के बारे में बताया गया है। इन टोटकों को आजमाकर देखने से कई लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है और यह आपके साथ भी हो सकता है। ये टोटके बेहद आसान और उपयोगी हैं, जो हर तरह की परेशानियों को हवा में उड़ा देते हैं। आइए जानते हैं इन टोटकों के बारे में...

धन धान्य में वृद्धि के लिए करें यह टोटका

घर में बरकत नहीं हो रही है, पता नहीं चलता पैसा कहां से आया और कहां चला गया तो इसके लिए आप मंगलवार के दिन लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली ले लें। इसके बाद इन सभी चीजों को लाल कपड़े में बांधकर एक सप्ताह के लिए घर के मंदिर में रख दें और हर रोज धूप बत्ती करें। एक सप्ताह बाद लाल रंग की पोटली को घर या कारोबार की तिजोरी में रख दें, ऐसा करने से बचत होने लगेगी। फिर 43 दिनों बाद इस सामान को जल में प्रवाहित कर दें, ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है।

करियर में उन्नति के लिए करें यह टोटका

नौकरी व कारोबार में उन्नति के लिए शनिवार के दिन पीपल का पत्ता लें और उसको गंगाजल से धो लें। अगर गंगाजल नहीं है तो आप दूध का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर उस पत्ते को साफ जगह रख दें। ऐसा ही आप अगले शनिवार को भी करें और जब सात शनिवार को सात पत्ते हो जाएं तो इस सातों पत्तों पर हनुमानजी का नाम लिखकर नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से करियर में तरक्की होती है और सभी तरह की अड़चन से मुक्ति मिलती है।

खुद का मकान बनाने के लिए करें यह टोटका

जो व्यक्ति लाख प्रयत्न करने के बाद खुद का मकान या दुकान नहीं बना पा रहे हैं तो यह टोटका आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इसके बाद आप शुक्रवार से लेकर रविवार तक यानी तीन दिन तक किसी गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को खाना खिलाते रहें और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से व्यक्ति की जल्द ही संपत्ति हो जाएगी।

धन प्राप्ति के लिए करें यह टोटका

शनिवार के दिन एक रोटी के ऊपर नीचे सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें और घर में तोता अवश्य पालें। साथ ही हर अमावस्या की शाम को विकलांग व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं। धन प्राप्ति के लिए यह टोटका काफी कारगर साबित होगा।

मनोकामना पूर्ति के लिए करें यह टोटका

बरगद के पेड़ के पत्ते पर सुबह अपनी मनोकामना लिख दें और फिर उसको प्रवाहित कर दें, ऐसा आप लगातार 11 दिनों तक करते रहें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी और अटके हुए काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही सात दिनों तक अखंडित लौंग को सरसों के दीपक में रखकर जलाएं। ऐसा करने से आपकी अधूरी इच्छा पूरी होगी और जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

शनि जयंती पर लगाएं इन चीजों का भोग, शनि देव होंगे प्रसन्न

पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

6 जून 2024 शनि देव की कृपा पाने का शुभ अवसर है, इस दिन शनि जयंती मनाई जाएगी. इस तिथि पर पूजा करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्यों को गति मिलती है. शनि देव जिन पर प्रसन्न होते हैं उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं. कोई काम में बाधा नहीं आती. शनि जयंती पर शनि देव का आशीर्वाद पाना है तो उनके प्रिय भोग जरुर अर्पित करें. जानें शनि देव को किन चीजों का भोग लगाएं.

शनि जयंती पर लगाएं इन चीजों का भोग

काली उड़द - शनि देव का काले रंग की वस्तु बेहद प्रिय है शनि जयंती पर भोग में काली खड़ी उड़द की दाल का हलवा बनाकर भोग लगाएं. शनि देव को मीठे पकवान पसंद है.

उड़द के लड्डू का भोग - शनि जयंती पर उड़द की दाल के लड्डू का भोग लगाना शुभ माना जाता है. मान्यता है इससे शनि प्रसन्न होकर समस्त संकट दूर करते हैं.

काले तिल के पकवान - शनि देव की पूजा में काले तिल बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं. शनि देव को भोग में काले तिल के लड्डू चढ़ाए या फिर मावे की मिठाई बनाकर उसमें काले तिल डालें. मान्यता है इससे शनि की अशुभता दूर होती है. शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं. साथ ही पितृ दोष दूर होता है.

गुलाब जामुन - शनि देव को गुलाबजामुन या मीठी पूड़ी का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है. माना जाता है कि इस भोग से शनि देव का कोप शांत होता है.

ज्येष्ठ अमावस्या क्यों है विशेष, इस दिन ऐसा क्या करें कि खुल जाएं भाग्य

पंडित कपिल पाराशर
बनारस वाले ज्योतिष आचार्य वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

हिंदू धर्म में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को महत्वपूर्ण माना गया है. इसे ज्येष्ठ अमावस्या भी कहा जाता है. इस बार ज्येष्ठ अमावस्या यानी 6 जून को मनाई जाएगी.

इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है. इस दिन शनि देव की विशेष पूजा करने का विधान है. ज्येष्ठ अमावस्या का दिन शनि दोष से मुक्ति के लिए बहुत उत्तम माना जाता है.

हिन्दू धर्म में दान-पुण्य और पितरों की शांति के लिए किये जाने वाले पिंड दान और तर्पण के लिए अमावस्या को ज्येष्ठ बहुत शुभ माना गया है.

इस दिन नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए. इसके बाद बहते जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए.

इस दिन किए गए उपायों से शनि के अशुभ प्रभावों से बचाव होता है. यह उपाय सुख-समृद्धि के रास्ते खोलते हैं और इससे भाग्य का साथ मिलता है.

शनि जयंती के दिन मंदिर में जाकर शनि देव के चरणों का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है. शनि देव को तेल, सिंदूर, कुमकुम, काजल, अबीर, गुलाल और नीले या काले फूल अर्पित करें.

इस दिन शनि देव की पूजा के बाद शनि मंत्र की एक माला का जाप करें और शनि चालीसा का पाठ करें. शनि जयंती पर शनि मंदिर में तेल के दीये जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है.

ग्रहों के बुरे प्रभाव से मिलेगी मुक्ति, करें काल भैरव से जुड़े ये उपाय

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

भगवान शिव का रूद्र अवतार काल भैरव देव को माना जाता है। मान्यता है कि बाबा भैरव की पूजा करने से शत्रुओं का भय नहीं रहता। कई भक्त बाबा काल भैरव की विधि-विधान से पूजा करते हैं। काले कुत्ते का संबंध बाबा काल भैरव से ही माना जाता है। ऐसे में अगर काले कुत्ते से जुड़े कुछ उपाय कर लिए जाएं, तो आपको भैरव देव की कृपा मिलेगी।

काले कुत्ते को खिलाएं रोटी

काले कुत्ते को खाना खिलाने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से राहु-केतु के दुष्प्रभाव को भी खत्म किया जा सकता है। इसके लिए शनिवार के दिन कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलानी चाहिए। कुंडली में केतु कमजोर होने पर नियमित रूप से काले कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। यह दूध मीठा नहीं होना चाहिए।

हर शनिवार की रात करें ये उपाय

प्रत्येक शनिवार की रात को काले कुत्ते को दूध और रोटी देनी चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही शनि की महादशा, शनि ढैय्या और साढ़ेसाती का प्रभाव भी कम हो जाता है। इस उपाय को करने से हर काम में सफलता मिलने लगती है।

कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए

जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, उन्हें घर में काला कुत्ता पालना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। काले कुत्ते को रोज रोटी खिलानी चाहिए। इस तरह से कालसर्प दोष का प्रभाव कम होता है और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके विपरीत काला कुत्ता पालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और बुरी नजर से भी बचा जा सकता है।

कब मनाई जाएगी महेश नवमी

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

सनातन पंचांग के अनुसार, महेश नवमी 15 जून को पड़ रही है। यह त्योहार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही कार्यों में सफलता पाने के लिए व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि माहेश्वरी समुदाय की वंशावली की उत्पत्ति ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई थी। इसलिए इस दिन माहेश्वरी समाज के लोग भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, महेश नवमी पर दुर्लभ वरियान योग बन रहा है। इसके साथ ही कई अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं। इन योगों में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।

वरियान योग- ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर वरियान योग बन रहा है। यह योग शाम 08 बजकर 12 मिनट से बन रहा है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वरियान योग में भी भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं।

रवि योग- महेश नवमी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। यह योग सुबह 08 बजकर 14 मिनट पर बन रहा है और अगले दिन यानी गंगा दशहरा पर सुबह 05 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होता है। रवि योग में भगवान शिव की पूजा करने से स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है।

शिव वास योग- ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को शिव वास योग बन रहा है। यह योग पूरे दिन रहेगा। यह योग 16 जून को सुबह 02 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगा। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से भक्त को मनचाहा वर मिलता है। इसके अलावा बालव और कौलव करण का भी योग बन रहा है।

रेड सी संकट से बढ़ गए फ्रिज, एसी के दाम, कंपनियों ने डीलर्स को भेजी नई रेट लिस्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

भीषण गर्मी के बीच पसीने छुड़ाने वाली खबर है। उपभोक्ताओं को फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, पंखे, किचन अप्लायंस, वायर और पंप जैसे इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए 2-5% अधिक खर्च करना पड़ेगा। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्ज के अनुसार, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, हैवेल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और वी-गार्ड इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख निर्माताओं ने या तो कीमतें बढ़ाई हैं या अपने डीलरों को सूचित किया है कि वे ऐसा करने वाले हैं। उनके मुताबिक, इसके पीछे कई कारण हैं। कॉपर और एल्यूमीनियम जैसी प्रमुख वस्तुओं के दामों में 20-25 फीसदी की बढ़ोतरी, पिछले दो-चार महीनों में लाल सागर संकट के कारण माल ढुलाई लागत में तेजी के अलावा रुपये के अवमूल्यन से भाव बढ़ने का ताजा दौर लगभग नौ महीने बाद आया है। देश की दूसरी सबसे बड़े घरेलू उपकरण निर्माता कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने गुरुवार को अपने ट्रेड पार्टनर्स को व्हाट्सएप मैसेज के जरिये इस बारे में सूचित किया है। उसने बताया है कि रुपये के अवमूल्यन से इनपुट लागत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए वह होम एप्लायंस कैटेगरी में जून से 2.5% की कीमत बढ़ोतरी पर विचार कर रही है।

केबल और वायर हुए महंगे

हैवेल्स के एमडी अनिल राय गुप्ता ने हमारे सहयोगी इकनॉमिक टाइम्स को बताया कि कंपनी ने इस महीने केबल और तारों की कीमतें बढ़ाई हैं। पिछली तिमाही में दाम बढ़ाए गए थे। उन्होंने कहा कि तांबा और एल्यूमीनियम की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण एयर-कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की कीमतें 5-7% तक बढ़ सकती हैं।

गुप्ता ने कहा, 'कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम होते हैं। लिहाजा, हमें इनपुट लागत में बढ़ोतरी को पास करना पड़ता है। केबल तार के लिए मार्जिन और भी कम होता है। इसलिए हमें कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं।' हैवेल्स लॉयड अप्लायंसेस ब्रांड की भी मालिक है।

कम्प्रेसर जैसे कंपोनेंट की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा टेलीविजन में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल पैनल के दामों में भी पिछले दो महीनों में 5-6% तक इजाफा हुआ है। जबकि माल ढुलाई लागत दो से तीन गुना बढ़ गई है। कंपनियों ने पहले विदेशी विनिमय दरों को रुपये 81-82 प्रति डॉलर पर कंपोनेंट के आयात के लिए स्टैंडर्ड बनाया था, लेकिन रुपया और अधिक टूट गया।

दाम बढ़ाने को मजबूर हैं कंपनियां

गोदरेज एप्लायंसेस के बिजनेस हेड, कमल नंदी ने कहा, 'इनपुट लागत पर कुल प्रभाव लगभग 2-3% है। कीमत बढ़ोतरी जरूरी है।' टेलीविजन निर्माता भी कीमत बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। कुछ छोटे ब्रांड जून में 4-6% की बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं।

ग्रेट ईस्टर्न रिटेल के निदेशक पुलकित बैद ने कहा, 'छोटी अवधि में बाजार मूल्य वृद्धि को बिना मांग पर प्रभाव डाले एडजस्ट कर लेगा। लेकिन, एक बार जब ग्रीष्मकालीन मांग धीमी हो जाएगी, तो ब्रांड्स को कीमतों को फिर से सुधारना पड़ सकता है।'

बजाज इलेक्ट्रिकल्स के सीईओ अनुज पोद्दार ने 14 मई को विश्लेषकों से कहा था कि कंपनी 16 मई से कीमतें बढ़ाएगी। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज ने इस महीने पंखे और पंप की कीमतें 2% बढ़ाई हैं।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने मई 2024 में 25,273 गाड़ियां बेचीं, 24% की वृद्धि

बैंगलोर। आईपीटी नेटवर्क

अपने मजबूत और स्थिर प्रदर्शन को रेखांकित करते हुए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने मई 2024 के महीने में 25,273 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। यह मई 2023 की तुलना में 24% की साल-के-मुकाबले-साल की वृद्धि है। तब कंपनी ने 20,410 इकाइयाँ बेची थीं। मई महीने में, घरेलू बिक्री 23,959 गाड़ियों तक पहुँच गई। इसमें 1,314 इकाइयों का निर्यात भी शामिल है। कंपनी ने अप्रैल 2024 की तुलना में भी 23% की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान 20,494 गाड़ियों की बिक्री हुई थी। इसके अलावा, यह उपलब्धि कैलेंडर वर्ष 2024 के पहले पांच महीनों में 48% की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाती है, जिसमें कुल बिक्री 1,22,776 गाड़ियों तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 82,763 गाड़ियां थी।

कंपनी के मजबूत प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के बिक्री-सेवा-उपयुक्त कार व्यवसाय के वाइस प्रेसिडेंट श्री सबरी मनोहर नेकहा, 'हम पिछले वर्ष की तुलना में 24३ की वृद्धि दर्ज करके मई 2024 के महीने में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज करना जारी रखते हैं। हमेशा कायम रहने वाले हमारे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण ने हमें अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को समझकर उत्पादों और सेवाओं की एक विविध श्रृंखला की पेशकश करके हमेशा आगे रहने के लिए प्रेरित किया है। हम टच पॉइंट्स को बढ़ाकर और आनंददायक स्वामित्व अनुभव बनाने के उद्देश्य से अभिनव मूल्य-वर्धित सेवाओं को क्यूरेट करके अपनी ग्राहक-केंद्रितता को सक्रिय करना जारी रखेंगे।

टाइम मैगजीन लिस्ट: दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में रिलायंस के अलावा और कौन भारतीय फर्में?

नई दिल्ली। एजेंसी

मशहूर अमेरिकी मैगजीन टाइम (Time) ने साल 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है। टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में तीन भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप को टाइम की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की टॉप 100 लिस्ट में जगह मिली है। यह भारतीय कंपनियों की वैश्विक पहुंच और प्रभाव का प्रमाण है कि वे विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

इस लिस्ट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स और पायनियर्स शामिल हैं। रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटन्स कैटेगरी में स्थान मिला है। जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी के लिए चुना गया है। प्रत्येक कैटेगरी में 20 कंपनियों को शामिल किया गया है।

रिलायंस के बारे में क्या कहा?

टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 'इंडियाज जगरनॉट' की उपमा दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर टाइम मैगजीन ने लिखा है कि कपड़ा और पॉलिएस्टर कंपनी के रूप में शुरू हुई रिलायंस आज एक विशाल और जीवंत बिजनेस ग्रुप है। साथ ही यह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी भी बन गई है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में कंपनी के पास एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम सहित कई बिजनेस हैं। भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी और टेक जाइंट जियो प्लेटफॉर्म्स ने 2021 में इस लिस्ट में जगह बनाई थी। टाइम मैगजीन ने रिलायंस और डिज्नी सौदे का भी जिक्र किया है। मैगजीन का कहना है कि 8.5 अरब डॉलर का यह सौदा भारत के तेजी से बढ़ते स्ट्रीमिंग बाजार पर रिलायंस की पकड़ मजबूत करेगा।

सीरम इंस्टीट्यूट और टाटा ग्रुप की भी तारीफ

टाइम मैगजीन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता के रूप में शामिल किया है। कंपनी हर साल 3.5 अरब खुराक बनाती है। कोविड महामारी के वक्त सीरम के टीकों ने लाखों जिंदगियां बचाई थीं। टाटा ग्रुप के बारे में टाइम ने कहा कि टाटा समूह ने भारत की पुरानी कंपनियों में से एक है। इसका विशाल पोर्टफोलियो स्टील, सॉफ्टवेयर, घड़ियों, सबसी केबल और रसायनों से लेकर नमक, अनाज, एयर-कंडीशनर, फैशन और होटल तक फैला हुआ है। टेक निर्माण, एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स में निवेश करके समूह एक टेक कंपनी बन रहा है। 2023 में यह आईफोन को असेंबल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी।

Toll Tax: महंगाई का बड़ा झटका! एनएचएआई ने देश के सभी हाईवे पर बढ़ाया टोल

नई दिल्ली। एजेंसी

आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। अब हाईवे पर सफर करने वालों की जेब ज्यादा ढीली होगी। देशभर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल दरों में इजाफा किया है। एनएचएआई ने टोल दरों में 5 फीसदी की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अब हाईवे पर सफर करने वालों को सोमवार से ज्यादा रुपयों का भुगतान करना होगा। राजमार्ग उपयोगकर्ता शुल्क का वार्षिक संशोधन पहले एक अप्रैल से लागू होना था। लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण वृद्धि स्थगित कर दी गई थी। वार्षिक संशोधन औसतन पांच प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है।एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, 'नया उपयोगकर्ता शुल्क तीन जून, 2024 से लागू होगा।' टोल शुल्क में यह परिवर्तन थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में परिवर्तन से जुड़ी दरों को संशोधित करने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 855 उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाता है। टोल की दरों में इस इजाफे का असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जून की शुरुआत होते ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। लोकसभा चुनावों के चलते टोल की दरों में ये इजाफा देर से किया गया है। पहले टोल दरों में ये बढ़ोतरी अप्रैल में होने जा रही थी।

अमेरिका-इंग्लैंड नहीं इस देश से भारत में आया सबसे ज्यादा विदेशी निवेश, आंकड़े देखकर रह जाएंगे दंग

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत को बीते वित्त वर्ष (2023-24) में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है। हालांकि, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच देश में विदेशी निवेश के प्रवाह में 3.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। हालांकि, 2023-24 में सिंगापुर से एफडीआई प्रवाह 31.55 प्रतिशत घटकर 11.77 अरब डॉलर पर आ गया है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने उस देश (सिंगापुर) से सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), केमैन आइलैंड, जर्मनी और साइप्रस सहित प्रमुख देशों से एफडीआई इक्विटी प्रवाह में कमी आई। हालांकि, नीदरलैंड और जापान से निवेश बढ़ा है। वित्त वर्ष 2018-19 से सिंगापुर, भारत के लिए ऐसे निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा था। 2017-18 में भारत ने मॉरीशस से सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित किया था।

इस वजह से खूब मिल रहा विदेशी निवेश

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत-मॉरीशस कर संधि में संशोधन के बाद सिंगापुर, भारत में निवेश के लिए पसंदीदा क्षेत्र के रूप में उभरा है। डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि दुनिया के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से एक के रूप में सिंगापुर उन वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करता है जो एशिया में निवेश करना चाहते हैं। मजूमदार ने कहा, "हाल ही में रीट विनियम 2014 में संशोधन जैसी भारत की पहल ने सिंगापुर स्थित निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। यही कारण है कि भारत को सिंगापुर से ऊंचा एफडीआई मिल सकता है।" उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि 2024-25 के उत्तरार्ध में भारत में एफडीआई में तेजी आएगी।

विकासशील देशों में लगा रहे पैसा

शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार संजीव मल्होत्रा ने कहा कि सिंगापुर और मॉरीशस ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उपयोग वैश्विक निवेशक भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अपना पैसा लगाने के लिए करते हैं। मल्होत्रा ने कहा, "हालांकि, ऐसे कई भू-आर्थिक और राजनीतिक कारक हैं जिनकी वजह से सिंगापुर ने हाल के दिनों में अधिक महत्व हासिल की है, लेकिन भारत के लिए एफडीआई में उसके सबसे ऊपर रहने का कारण कर है।" उन्होंने कहा कि सिंगापुर में बहुत प्रतिस्पर्धी घरेलू कर व्यवस्था है और उसका नियामकीय ढांचा काफी दक्ष है।

डी बीयर्स ग्रुप द्वारा अपने 'बिल्डिंग फॉरएवर' लक्ष्यों की स्थिति पर एक प्रगति रिपोर्ट पेश की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

डी बीयर्स ग्रुप द्वारा अपने 'बिल्डिंग फॉरएवर' सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रिपोर्ट पेश गई, जिसमें प्रमुख रूप से दो वर्ष पूर्व 5000 महिलाओं और लडकियों को एऊशें (साईंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एवं मैथेमेटिक्स) में शामिल करने का लक्ष्य हासिल करना, बोत्सवाना में एक प्रमुख डायमंड फॉर डेवलपमेंट फण्ड स्थापित करने पर सहमति, हाल ही में मान्य विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के समर्थन में प्रमुख नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं और अग्रणी डायमंड ट्रैसेबिलिटी प्लेटफार्म ट्रैकर के विकास को आगे बढ़ाना शामिल है। 2020 में स्थापित 'बिल्डिंग फॉरएवर' डी बीयर्स ग्रुप का ब्लूप्रिंट है, जो उन लोगों और स्थानों के लिये, जहां इसके डायमंड्स खोजे जाते हैं, जो हितधारकों की प्राथमिकताओं के साथ निकटता से जुडे होते हैं, के लिये सकारात्मक और स्थाई प्रभाव पैदा करने हेतु प्रयासरत है। इसमें चार प्रमुख क्षेत्र नैतिक मूल्यों का नेतृत्व करना, सम्पन्न समुदायों के लिये साझेदारी करना, प्राकृतिक संसार की रक्षा करना और समान अवसर में तेजी लाना शामिल है, जहां कम्पनी अपने साझेदार देशों और व्यापक प्राकृतिक डायमंड मूल्य श्रृंखला के भीतर सार्थक प्रगति को सपोर्ट करने के लिये काम कर रही है।

2023 के दौरान डी बीयर्स ने मेजबान कम्युनिटीज़ में सतत् विकास के परिणामों का सपोर्ट करने के लिये सरकारी भागीदारी और गैर-सरकारी संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखा। एक बड़ी उपलब्धी बोत्सवाना सरकार के साथ एक 10 वर्षीय नवीन सेल्स एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में डेवेलपमेंट फण्ड के लिये डायमंड्स की स्थापना के लिये एक साझा प्रतिबद्धता की घोषणा करना था। डी बीयर्स की एक पहल (75 मिलियन यूएस डॉलर), 'एक बिलियन पुला, की प्रतिबद्धता के साथ इस फण्ड का लक्ष्य देश की उभरती हुई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करना और इसके दीर्घकालिक आर्थिक विविधीकरण में तेजी लाना है।

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस का 'सुनाओ दर्द-ए-किराएदारी' अभियान

गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में गूंजेगा अपने घर की उम्मीद का नारा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस ने किराएदारी की पीड़ा को मिटाने के लिए एक अनूठा कैंपेन शुरू किया है - 'सुनाओ दर्द-ए-किराएदारी' जिसका उद्देश्य गांवों और कस्बों में आम जनता को किराएदारी की समस्या से मुक्त करना और उन्हें अपना घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, लोगों को जागरूक करना कि उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस किराएदारी से मुक्ति का एक आसान और किफायती समाधान प्रदान करता है। इस अभियान के अंतर्गत एक वैन आसपास के गांवों और कस्बों में घूमेगी, लोगों को किराएदारी की पीड़ा से मुक्ति पाने के तरीकों को मनोरंजक खेलों के माध्यम से बताएगी जैसे आसान किश्तों में ऋण कैसे प्राप्त करें, साथ ही सफल कहानियां साझा की जाएंगी जो लोगों को प्रेरित करेंगी और उन्हें दिखाएंगी कि कैसे हाउसिंग फाइनेंस ने उनके सपनों का घर खरीदने में उनकी मदद की है। उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर आशुतोष शर्मा ने बताया कि उन्होंने जन सामान्य के बीच मौजूद 'किराएदारी की समस्या' को बारीकी से समझते हुए इसके समाधान पर काम किया है। वे आगे कहते हैं - अपने सपनों का घर खरीदने का समय आ गया है, क्योंकि आपका घर, आपका सपना, अब हमारी जिम्मेदारी है! उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस आसान किश्तों में ऋण प्रदान करता है ताकि लोग अपना घर खरीद सकें, ऐसी ऋण योजनाएं बनाता है, जो सस्ती और लचीली हैं ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार एक योजना चुन सकें। इसके साथ ही, उम्मीद फाइनेंस की अनुभवी टीम आपको ऋण प्रक्रिया में हर चरण में सहायता करेगी।

विश्व पर्यावरण दिवस पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कई शहरों में किया वृक्षारोपण अभियान

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) ने पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक व्यापक 'वृक्षारोपण' अभियान का आयोजन किया। वृक्षारोपण अभियान जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, रायपुर, अहमदाबाद, रोहतक, बेंगलुरु, इंदौर, मुंबई, पुणे और कोलकाता सहित पूरे भारत में ग्यारह स्थानों पर चलाया गया।

5 जून को दुनियाभर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम भूमि बहाली (लैंड रेस्टोरेशन), मरुस्थलीकरण और भविष्य के लिए सूखे का प्रबंधन (सूखे से बचाव) है और नारा है 'हमारी भूमि हमारा भविष्य'। वृक्षारोपण लैंड रेस्टोरेशन यानी भूमि बहाली में मदद करता है, मरुस्थलीकरण (जमीन का रेतीला होना या बंजर होना) से बचाता है, और इकोसिस्टम को सूखे से बचाता बनाता है, इसलिए एयू एसएफबी ने वृक्षारोपण' अभियान का आयोजन किया।

इसके महत्व पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाउंडर, एमडी और सीईओ, संजय अग्रवाल ने कहा, 'यह वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण और ससटेनेबले प्रथाओं के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप है। एयू एसएफबी 'पर्यावरण' को एक प्रमुख हितधारक मानता है और इसलिए हमने बोर्ड की सस्टेनेबिलिटी कमेटी के मार्गदर्शन में अपने सस्टेनेबिलिटी प्रयासों को बढ़ावा दिया है। एक बैंक के रूप में हम एक स्थायी भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं।' एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ई.एस.जी.) पहल में अग्रसर है, जो प्रमुख सस्टेनेबिलिटी प्लेटफार्म पर इसकी बढ़ी हुई रेटिंग से नजर आता है। यह मान्यता सस्टेनेबिलिटी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता और बैंकिंग इंडस्ट्री में उसके बेहतरीन प्रयासों को भी दर्शाती है।

मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर लगाया प्रतिबंध

एजेंसी

मालदीव ने गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट वाले आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार ने इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले को लागू करने के लिए मंत्रियों की एक विशेष कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है।

मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है।' प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'कैबिनेट के फैसले में इजरायली पासपोर्ट धारकों को मालदीव में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक कानूनों में संशोधन करना और इन प्रयासों की निगरानी के लिए एक कैबिनेट सब-कमिटी की स्थापना करना शामिल है।'

मालदीव में आते हैं 10 लाख पर्यटक

मुइज्जू सरकार ने ये फैसला गाजा पर इजरायली सेना के हमले को लेकर मालदीव के लोगों में लगातार बढ़ रहे गुस्से को देखते हुए लिया है। मालदीव में हर साल दस लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। इसमें इजरायल से लगभग 15,000 पर्यटक शामिल हैं। वहीं, मालदीव सरकार ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए फंड जुटाने और उसके समर्थन के लिए मुस्लिम देशों के साथ चर्चा करने का भी फैसला किया है। कहा जा रहा है कि UNRWA के जरिए फिलिस्तीन नागरिकों के लिए फंड इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विशेष दूत नियुक्त करने का फैसला किया है, जहां फिलिस्तीन को मालदीव की मदद की सख्त जरूरत है।

ऐतिहासिक कदम

मालदीव ने 1990 के दशक की शुरुआत में इजरायली नागरिकों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया था और 2010 में राजनयिक संबंध बहाल कर दिए थे। हालांकि, एएफपी ने बताया कि 2012 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के अपदस्थ होने के बाद संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास बंद हो गए।

इजरायली पर्यटन में गिरावट

मालदीव की अर्थव्यवस्था की आधारशिला पर्यटन में इजरायली पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष के पहले चार महीनों में 88 प्रतिशत की गिरावट आई है।

भारत 4, अमेरिका 2, जापान 2, चीन 0... इस लिस्ट को देखकर गर्व से फूल जाएगा आपका सीना

नई दिल्ली। एजेंसी

एमआरएफ (MRF) का नाम तो आपने सुना ही होगा। टायर बनाने वाली चेन्नई की इस कंपनी का शेयर भारत का सबसे महंगा स्टॉक है। अभी कंपनी के एक शेयर की कीमत करीब एक लाख 25 हजार रुपये है। लेकिन यह टायर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। देश की सबसे बडी टायर कंपनी का खिताब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज () के नाम है। यह ऑफ-हाइवे टायर बनाती है। यानी यह एग्रीकल्चर टायर (ट्रैक्टर्स), इंडस्ट्रियल टायर (क्रेन, ग्रेडर) और ओटीआर टायर बनाती है। दुनिया की टॉप 13 कंपनियों में भारत की सबसे ज्यादा चार कंपनियां शामिल हैं। इनमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मद्रास रबर फैक्ट्री, अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) और सिएट (CEAT) शामिल हैं। इस लिस्ट में चीन की कोई भी कंपनी शामिल नहीं है। अमेरिका और जापान की दो-दो कंपनियों को इस लिस्ट में जगह मिली है।दुनिया में टायर बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में टॉप पर जापान की कंपनी ब्रिजस्टोन (Bridgestone) है। फ्रांस की कंपनी मिशेलिन (Michelin) इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जर्मन कंपनी कॉन्टिनेंटल (Continental) है। भारत की कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चौथे और एमआरएफ पांचवें नंबर पर है। इटली की कंपनी पिरेली (Pirelli) छठे नंबर पर है। अमेरिकी कंपनी गुडईयर (Goodyear) इस लिस्ट में सातवें, दक्षिण कोरिया की हैनकुक टायर (Hankook Tire) आठवें, भारत की अपोलो टायर (Apollo Tyres) नौवें, जापान की टोयो टायर (Toyo Tire) दसवें, फिनलैंड की नोकियन टायर्स (Nokian Tyres) 11वें, भारत की सिएट (CEAT) 12वें और टाइटन इंटरनेशनल (Titan International) 13वें नंबर पर हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।